OFFICIAL TEXT

Public Affairs Office of the U.S. Embassy, New Delhi

Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi 110021 Tel: 91-11-24198000 Ext.8819 Fax: 91-11-24198817
Visit us at: <http://usembassy.state.gov/delhi.html>

व्हाइट हाउस

प्रेस सेक्रेटरी ऑफिस

---

18 जुलाई, 2005

राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संयुक्त वक्तव्य

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बुश ने आज दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने तथा विश्वव्यापी भागीदारी स्थापित करने के लिए अपने संकल्प की घोषणा की। मानवीय स्वतंत्रता के मूल्यों, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रों के अगुआ के रूप में भारत और अमेरिका के बीच नए रिश्तों से पूरी दुनिया में स्थायित्व, लोकतंत्र, समृद्धि तथा शांति हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। इससे आपसी चिंताओं तथा हितों के मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए मिलकर कार्य करने की हमारी क्षमता में वृद्धि होगी।

समान मूल्यों तथा हितों पर आधारित निर्माण का दोनों नेताओं का संकल्प:

- लोकतांत्रिक मूल्यों की उन्नति और खुलापन और बहुलता चाहने वाले समाज में लोकतांत्रिक क्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का निर्माण करना।
- आतंकवाद के साथ कड़ाई से निबटना। उन्होंने आतंकवाद से निबटने के लिए दोनों देशों के बीच सक्रिय जोरदार सहयोग तथा इस दिशा में किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समर्थन पर प्रसन्नता व्यक्त की। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है और इससे हम हर जगह लड़ेंगे। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध सितंबर के संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन के निष्कर्ष के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री की यात्रा नेक्स्स स्टेप्स इन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप (एनएसएसपी) योजना के अनुरूप है जिसकी शुरुआत जनवरी 2004 में की गई थी। दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि इससे द्विपक्षीय गतिविधियों के विस्तार तथा अंतरिक्ष, नागरिक उपयोग की परमाणु ऊर्जा तथा दोहरे प्रयोग की प्रौद्योगिकी के व्यापार हेतु आधार मिलता है।

भारत-अमेरिकी संबंधों पर साझी दृष्टि की रूपरेखा, और मजबूत दीर्घकालीन लोकतंत्र के हमारे संयुक्त उद्देश्य हेतु दोनों नेता निम्नलिखित पर सहमत हुए:

अर्थव्यवस्था के लिए

- भारत अमेरिकी आर्थिक वार्ता को पुन: शुरू करने तथा एक निजी क्षेत्र की ऊर्जा को नियंत्रित करने तथा द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए सीईओ फोरम बनाना।
- व्यापार, निवेश तथा प्रौद्योगिकी सहयोग के द्वारा आर्थिक विकास में सहयोग करना तथा उसमें तेजी लाना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत् विकास के लिए पूर्वापेक्षित भारत की बुनियादी संरचना के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। भारत, निवेश वातावरण को बढ़ावा दे रहा है जिससे निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
- शिक्षण, शोध, सेवा और वाणिज्यिक संबंधों पर केंद्रित भारत-अमेरिकी कृषि पर जानकारी योजना शुरू करना।

ऊर्जा एवं पर्यावरण के लिए

- ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा पर्याप्त, सस्ती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा टिकाऊ विकास के लिए जागरूकता की आवश्यकता की दृष्टि से भारत में स्थायी तथा कारगर ऊर्जा बाजार के विकास को बढ़ावा देना। इन मुद्दों पर भारत-अमेरिकी ऊर्जा वार्ता में विचार-विमर्श किया जाएगा।
- विकास अनिवार्यताओं की आवश्यकता तथा पर्यावरण सुरक्षा के उपाय, सफाई के विकास तथा विस्तार के प्रति प्रतिबद्ध, अधिक कारगर, सस्ती, और विविधतापूर्ण ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर सहमति।

लोकतंत्र और विकास के लिए

- नयी भारत-अमेरिकी विश्वव्यापी लोकतंत्र पहल के माध्यम से सहायता के इच्छुक देशों, लोकतंत्रों को विश्वसनीय और प्रभावी बनाने तथा इसकी बुनियाद को मजबूती प्रदान करने वाले संस्थानों तथा संसाधनों विकसित करना व सहायता प्रदान करना। भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक क्रिया-कलापों तथा क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे एवं नए संयुक्त राष्ट्र लोकतांत्रिक फंड में योगदान करेंगे।
- निजी क्षेत्रों तथा सरकारी संसाधनों, जानकारी तथा विशेषज्ञता के माध्यम से विश्व स्तर पर एचआईवी/एड्स से लड़ने हेतु सहयोग को मजबूत बनाने के प्रति प्रतिबद्ध।

अप्रसार तथा सुरक्षा हेतु

- रक्षा प्रौद्योगिकी सहित भविष्य के सहयोग के आधार पर भारत-अमेरिकी रक्षा संबंधों के नए ढांचे पर संतोष व्यक्त किया।

- जनसंहार के हथियारों के प्रसार को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में प्रमुख भूमिका अदा करने के लिए प्रतिबद्ध। भारत द्वारा जनसंहार के हथियारों के बारे में कानून (प्रीवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज बिल) अपनाने का अमेरिका ने स्वागत किया है।
- आपदा राहत कार्यक्रमों के लिए सहयोग को मजबूत बनाने हेतु सुनामी कोर ग्रुप के अनुभवों के आधार पर एक नई भारत-अमेरिकी आपदा राहत योजना शुरु करेंगे।

उच्च-प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष के लिए

- साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर, संयुक्त अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत-अमेरिकी उच्च-प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एचटीसीजी) बनाना, तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी की स्थापना।
- एनएसएसपी की मजबूत अप्रसार प्रतिबद्धताओं के आधार पर कुछ भारतीय संगठनों को डिपार्टमेंट आफ कॉमर्स की एन्टिटी लिस्ट से हटाना।

बढ़ती विश्वव्यापी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वच्छ एवं अधिक कारगर तरह से असैनिक परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझते हुए दोनों नेताओं ने भारत के असैनिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की विकास योजनाओं पर बातचीत की।

राष्ट्रपति बुश ने जनसंहार के हथियारों के प्रसार को रोकने के प्रति भारत के दृढ़संकल्प के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए भारत को आधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी संपन्न एक जिम्मेदार राष्ट्र बताया तथा कहा कि भारत को ऐसे अन्य राष्ट्रों की तरह ही लाभ और अवसर मिलने चाहिए। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बताया कि वह परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्यों को समझते करते हुए सभी असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए भारत के साथ कार्य करेंगे। राष्ट्रपति बुश कांग्रेस से अमेरिकी कानून तथा नीतियों को अनुकूल बनाने के समझौते का भी प्रयास कर रहे हैं। भारत के साथ सभी नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग और व्यापार संबंध बनाने हेतु अमेरिका अपने मित्रों तथा साथियों से भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अनुकूल बनाने हेतु विचार-विमर्श करेगा और इसके साथ-साथ तारापुर में परमाणु रिएक्टरों के सुरक्षा उपायों हेतु ईंधन आपूर्ति व अन्य पर शीघ्र विचार करेगा। इस दौरान अमेरिका अपने भागीदारों को भी इस निवेदन पर शीघ्रतापूर्ण विचार करने हेतु प्रेरित करेगा। भारत ने आईटीईआर में अपनी रुचि एवं योगदान की इच्छा व्यक्त की है। अमेरिका अपने भागीदारों से भारत की सहभागिता पर विचार करने हेतु विचार-विमर्श करेगा। अमेरिका जेनरेशन आईवी इंटरनेशनल फोरम में भाग लेने वाले देशों से भी भारत को सम्मिलित करने की दृष्टि से विचार-विमर्श करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पारस्परिक रूप से सहमत होगा। भारत उन जिम्मेदारियों तथा कार्यों को स्वीकार करने का इच्छुक है और परमाणु प्रौद्योगिकी संपन्न अमेरिका जैसे अन्य प्रमुख देशों के समान लाभ और अवसर चाहता है। इन जिम्मेदारियों तथा कार्यों में हैं-- असैनिक और सैनिक परमाणु केंद्रों और कार्यक्रमों को चरणबद्ध पद्धति से पहचान करना तथा उनमें भेद करना तथा अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) में अपनी असैनिक केंद्रों के बारे में एक घोषणा फाइल करना; स्वेच्छा से आईएईए के सुरक्षा उपायों के अंतर्गत अपने असैनिक परमाणु केंद्रों को रखने का निर्णय लेना; असैनिक परमाणु केंद्रों के लिए सम्मानपूर्वक एक अतिरिक्त

प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना और उसका पालन करना; भारत के परमाणु परीक्षण के एकपक्षीय निलंबन को जारी रखना; एक बहुपक्षीय फिसाइल मैटीरियल कट ऑफ ट्रीटी के निष्कर्ष के लिए अमेरिका के साथ कार्य करना; संवर्धन व पुनर्प्रसंकरण प्रौद्योगिकियां जिन देशों के पास नहीं हैं उनको इनका हस्तान्तरण को रोकना और इनके फैलाव को सीमित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करना; और व्यापक निर्यात नियंत्रण कानून और सहमति द्वारा परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाना तथा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) तथा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप (एनएसजी) के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के आश्वासन का स्वागत किया। दोनों नेता इन उपरोक्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक चरणबद्ध कार्यवाही हेतु आने वाले महीनों में कार्यसमूह स्थापित करेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस बात पर भी सहमत हुए कि वे राष्ट्रपति की 2006 में भारत यात्रा के समय इसके विकास की समीक्षा करेंगे।

दोनों नेताओं ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उनके देश परमाणु, रासायनिक, जैविकीय तथा विकिरणीय हथियारों सहित जनसंहार के हथियारों के प्रसार को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में प्रमुख भूमिका अदा करेंगे।

निकट संबंधों के आलोक और क्षेत्रीय व विश्व सुरक्षा बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका की मान्यता के आधार पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को 1945 से विश्व परिदृश्य में आए बदलाव को अभिव्यक्त करना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत की प्रमुख और बढ़ती भूमिका के अनुरूप ढल रहे हैं। दोनों नेताओं ने विश्व मंचों पर भारत और अमेरिका द्वारा अपने सहयोग को मजबूत बनाने की अपेक्षाएं व्यक्त कीं।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने भव्य स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार के लिए राष्ट्रपति बुश का धन्यवाद किया। उन्होंने राष्ट्रपति बुश को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

***